भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1448

12/12/2025 को उत्तरार्थ

विषय- भारत में खेती करने वाले परिवारों की औसत मासिक/दैनिक आय

1448. श्री संदोष कुमार पी

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में कृषि कार्य करने वाले परिवारों की औसत मासिक आय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में कृषि कार्य करने वाले परिवारों की औसत दैनिक आय का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कृषि कार्य करने वाले परिवारों की कम आय के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कृषि कार्य करने वाले परिवारों की औसत दैनिक और मासिक आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का आकलन समय-समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा संचालित "कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)" के माध्यम से किया जाता है। नवीनतम एनएसएस के 77वें दौर के सर्वेक्षण (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के अनुसार, जुलाई, 2018-जून, 2019 के कृषि वर्ष के संदर्भ में, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये प्रति माह अनुमानित है। जुलाई, 2018-जून, 2019 के कृषि वर्षों के लिए राज्यवार प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय का विवरण अनुबंध I पर दिया गया है। चूंकि कृषि परिवारों की आय पर पिछला सर्वेक्षण 2019 में किया गया था, इसलिए पिछले पांच वर्षों के लिए प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) एवं (घ): भारत सरकार किसानों के कल्याण को बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने समय-समय पर कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न नीतियां, सुधार, विकासात्मक कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित की हैं, ताकि उत्पादन बढ़ाकर, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करके और आय सहायता देकर देश के किसानों के कल्याण और आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। भारत सरकार ने किसानों की विकास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की है:

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
iii. संसाधन उपयोग दक्षता – उत्पादन लागत में कमी
iv. फसल गहनता में वृद्धि
v. उच्च मूल्य वाली कृषि की ओर विविधीकरण
vi. किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य
vii. अधिशेष जनशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण।

उपरोक्त सात उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के 21933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के लिए 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम का आशय उत्पादन में वृद्धि, किसानों के लिए लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता प्रदान करके किसानों का कल्याण करना है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, मार्केटिंग, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की थी। इन पहलों से पिछले पांच वर्षों में किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची अनुबंध II में दी गई है। घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में वर्ष 2011-12 (68वें दौर) के अनुमानों की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एमपीसीई की तुलना नीचे तालिका में दी गई है, जिसमें व्यय स्तरों में वृद्धि और इस अवधि के दौरान संबंधित वृद्धि प्रतिशत को दर्शाया गया है।

क्षेत्र	विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.)		विकास (%)
	2011-12 एनएसएस (68वां दौर)	2023-24	
ग्रामीण	1, 430	4, 122	188.2
शहरी	2, 630	6, 996	166.1

अनुबंध-I

"भारत में खेती करने वाले परिवारों की औसत मासिक/दैनिक आय" के संदर्भ में राज्य सभा में दिनांक 12.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 1448 के भाग (क) और (ख) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

कृषि वर्ष जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/पूर्वोत्तर राज्यों का समूह/ संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	आय (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	10,480
2	अरुणाचल प्रदेश	19,225
3	असम	10,675
4	बिहार	7,542
5	छत्तीसगढ़	9,677
6	गुजरात	12,631
7	हरियाणा	22,841
8	हिमाचल प्रदेश	12,153
9	जम्मू एवं कश्मीर	18,918
10	झारखंड	4,895
11	कर्नाटक	13,441
12	केरल	17,915
13	मध्य प्रदेश	8,339
14	महाराष्ट्र	11,492
15	मणिपुर	11,227
16	मेघालय	29,348
17	मिजोरम	17,964
18	नागालैंड	9,877
19	ओडिशा	5,112
20	पंजाब	26,701
21	राजस्थान	12,520
22	सिक्किम	12,447
23	तमिलनाडु	11,924
24	तेलंगाना	9,403
25	त्रिपुरा	9,918
26	उत्तराखंड	13,552
27	उत्तर प्रदेश	8,061
28	पश्चिम बंगाल	6,762
	पूर्वोत्तर राज्यों का समूह	**16,863**
	संघ राज्य क्षेत्रों का समूह	**18,511**
	अखिल भारतीय	**10,218**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों और परिवारों की जोत भूमि और पशुधन की स्थिति का आकलन, 2019

अनुबंध II

"भारत में खेती करने वाले परिवारों की औसत मासिक/दैनिक आय" के संदर्भ में राज्य सभा में दिनांक 12.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 1448 के भाग (ग) और (घ) तक के संबंध में उललिखित विवरण।

किसानों के कल्याण के लिए उत्पादन बढ़ाने, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करने और आय में सहायता उद्देश्यार्थ प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टार्ट-अप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

*****